सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2010-11

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

- **बजट घोषणा 2009–2010:** समस्त सरकारी विभागों के आयोजना बजट का 3 प्रतिशत भाग नागरिक केन्द्रित ई–प्रशासन हेतु सुनिश्चित किया गया है। ई–प्रशासन हेतु एक अलग बजट हेड खोला गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को **QSI (Quality Services International)** द्वारा दिनांक 11.02.2010 को आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
- दिनांक 18–19 फरवरी, 2010 को राज्य सरकार द्वारा जयपुर में 13वें राष्ट्रीय ई–शासन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन अभियोग विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। सम्मेलन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार को ई–संचार परियोजना हेतु सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए तथा प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल के लिए पुरस्कृत किया गया।
- दिनांक 10–12 मार्च, 2010 को **Electronics and Computer Software Export Promotion Council** द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के संरक्षण में **IndiaSoft 2010** कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 50 देशों के 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- **ई–मित्र :–** राज्य के सम्पूर्ण जिलों में ई–मित्र परियोजना क्रियान्वित कर दी गई है। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रियान्वित सी.एस.सी. परियोजना के समान है जो कि शहरी क्षेत्र में कियोस्क के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक 579 कियोस्कों के माध्यम से 1.09 करोड़ रूपये का लेन–देन किया गया।

- ई–मित्र परियोजना का ऑन लाइन प्रबोधन http://emitra.gov.in तथा http://urban.emitra.gov.in पर उपलब्ध है।

- **Chief Minister Information System (CMIS) (www.cmis.rajasthan.gov.in)-** मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकास कार्यों की कम्प्यूटर की

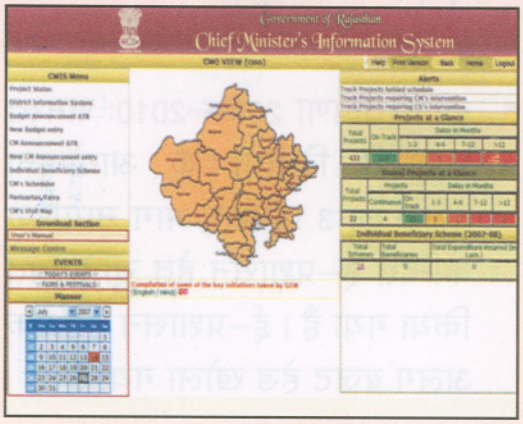

सहायता से तीव्र गति से समीक्षा करने के उद्देश्य से Chief Minister Information System (CMIS) का क्रियान्वयन किया गया। इसके माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, केन्द्रीय प्रवर्तित, राजकीय एवं अन्य वित्तीय सहायता से क्रियान्वित, का प्रबोधन किया जाता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओ, बजट घोषणाओं इत्यादि का प्रबोधन भी इस तंत्र द्वारा किया जाता है। जिलों में किये

जा रहे विकास कार्यों की जानकारी इस तंत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु समय समय पर उपलब्ध करवायी जाती है। वर्तमान में परियोजना का विकास करते हुये इसमें आवश्यकतानुसार 18 नये मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं।

- **आपदा प्रबंधन तंत्र (http://dmrd.rajasthan.gov.in)** आपदा राहत कार्यो का संचालन सुचारू एवं त्वरित गति से करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत आपदा प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित किया गया है। इस तंत्र के माध्यम से राज्य में राहत कार्यो के तहत की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर कहीं से और कभी भी निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सकता है।

- **स्वास्थ्य मित्र : टेलिमेडिसिन –** राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशिष्ट

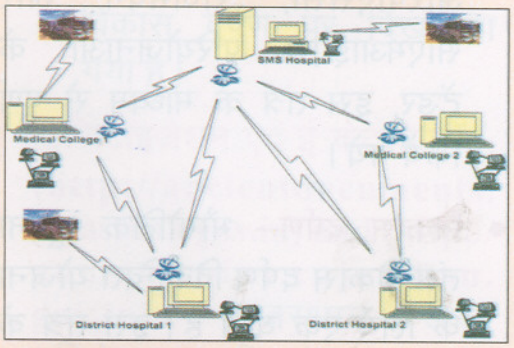

चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये इसरो (ISRO) की सहभागिता से राज्य में टेलिमेडिसिन नेटवर्क स्थापित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों पर स्थित 6 चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 31 जिला अस्पतालों के मध्य यह सुविधा सफलता पूर्वक आरंभ कर दी गई है। यह परियोजना 14 फरवरी 2006 से क्रियाशील है।

- **पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परियोजना (सारथी) –** पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी 259 उप पंजीयक कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। किसी भी एस.आर. कार्यालय के क्षेत्र में आने वाली स्थावर संपत्ती का पंजीकरण किसी भी स्थान से करवाने की व्यवस्था हेतु एप्लीकेशन सोफ्टवेयर विकसित कर जयपुर के 11 उप पंजीयक कार्यालयों में पायलट आधार पर परीक्षण हेतु क्रियान्वित कर दिया गया है। शेष कार्यालयों में पीपीपी मॉडल पर कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है।

- **भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण–** राज्य की सभी 241 तहसीलों के 68 लाख भू–धारियों के रिकोर्ड्स को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमाबंदियां जनता को कियोस्कों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- **वेट (VAT) स्वचालित तंत्र** (www.rajtax.gov.in) राज्य में वैट (VAT) स्वचालित तंत्र क्रियान्वित कर दिया गया है। इस परियोजना में e-payment एवं e-returns को फाइल करने की सुविधा भी है। वर्तमान में समस्त e-returns इलैक्ट्रानिक माध्यम से फाइल किये जा रहे हैं।

  - इस सुविधा के द्वारा 31 दिसम्बर, 2010 तक 12275.52 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया।

- **राज्य सरकार के विभागों में बैक एण्ड कम्प्यूटरीकरण –** वर्ष 2005 से हर वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम सें विभिन्न विभागों के बैकएण्ड कम्प्यूटरीकरण हेतु बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- **ई–क्रय तंत्र –** राजकीय विभागों में विभिन्न सामग्रीयों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से ई–प्रक्योरमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में जन स्वास्थ्य

अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस तंत्र के माध्यम से टेंडर किए जा रहे हैं। आदिनांक तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के 22 टेंडरों का, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 20 से अधिक टेंडर, राजकॉम्प के टीएडी, आरपीएससी, राजभवन और सीएमआईएस परियोजनाओं के टेंडर, इस तंत्र के माध्यम से पूर्ण किये गये।

- **विकास दर्पण–** भौगोलिक सूचना तंत्र बिकास दर्पण विकेन्द्रित योजना के लिये एक यन्त्र है। इस तंत्र के

द्वारा राज्य के 32 जिलों, 241 तहसीलों एवं 41000 गांवों का संपूर्ण नक्शा एवं सैन्सस 2001 के संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाये जाते है। वेब आधारित GIS एप्लीकेशन http://gis/rajasthan.gov.in भी विकसित की जा चुकी है।

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में इसका उपयोग कर 12 अभाव ग्रस्त जिलों व ग्रामों को नक्शे पर दिखलाने का अभिनव प्रयोग किया गया।
- नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) के लिये चिन्हित सभी गांवों को भी विकास दर्पण पर दिखलाया गया है।

- **डिजिटाइजेशन एवं ई केटलोगिंग ; (http://ancientdocuments.rajasthan.gov.in) and (http://ancientcoins.rajasthan.gov.in)**– राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान

प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर तथा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के पुरातत्व ग्रन्थ एवं दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है साथ ही पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग के प्राचीन एवं दुर्लभ सिक्कों के डिजिटाइजेशन एवं ई केटलोगिंग का कार्य किया जा रहा है।

- **Litigation Information, Traking & Evaluation System (LITES)** – इस परियोजना का विकास राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निबटारे के लिये किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2006 में किया गया। परियोजना के द्वारा 45 प्रशासनिक विभागों की 201 इकाईयों के लगभग 1100 अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.4 लाख मुकदमों का प्रबोधन किया जा रहा है।

- **विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग–** राज्य के 33 ज़िला–कलैक्टर कार्यालयों को विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग सुविधा द्वारा राज्य सचिवालय से जोड़ दिया गया है।
- **सैकलैन का विस्तार–** राज्य सचिवालय में स्थापित सैकलैन का विस्तार करते हुए विगत दो वर्षो में पशु धन भवन, सामाजिक न्याय एवं

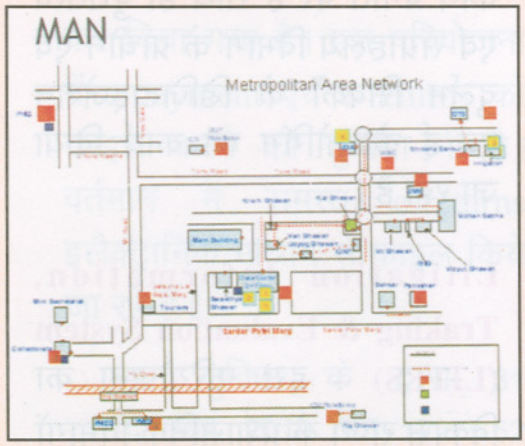

अधिकारिता भवन, स्वायत्त शासन भवन, निधी भवन, एस.एम.एस. अस्पताल, श्रम भवन, राज्य भण्डारण निगम भवन, स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान पुलिस अकादमी को जोडा गया जिससे जयपुर मेट्रोपोलिटन एरिया नैटवर्क से जुडे भवनों की संख्या 40 हो गई है। इस नेटवर्क का विस्तार करके एन.आई. सी. के तकनीकी सहयोग से समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

- **स्टेट डेटा सेन्टर–** राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं के केन्द्रिय भंडारण हेतु राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र (State Data Centre-SDC) कार्यशीलहैं। वर्तमान में राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द में 239 वेब साईट स्थापित कर कार्यशील

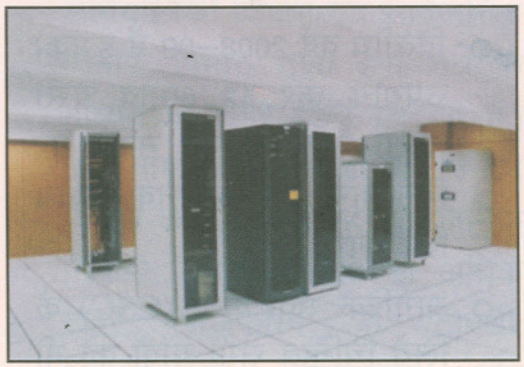

कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द में जी.आई.एस., ई–क्रय तंत्र, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए राजक्रेस्ट परियोजना के सर्वर एवं अन्य सरकारी विभागों की विभिन्न

परियोजनाओं के सर्वर सफलतापूर्वक निरन्तर कार्य कर रहें है।

- **Mobile V-SAT Van–** राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को सरकार से सुलभ संवाद स्थापित करने के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में दो Mobile V-SAT Van क्रियाशील कर दी गयी है। इस सुविधा का उपयोग इस वर्ष सितम्बर–अक्टूबर महिनों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य चेतना यात्रा में किया गया।

मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण–** ई–गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर आर.के.सी.एल.के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं। वर्ष 2008–09 से आदिनांक तक लगभग 20000 से अधिक कर्मचारियों / अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- इस वर्ष राज्य सेवा के सात अधिकारियों को TAPMI, मनिपाल में सरकारी खर्चे पर एक वर्षीय e-GPX कार्यक्रम के लिये भेजा गया है।
- इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कई नए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रारम्भ किया गया है जैसे कि e-Government project life Cycle, Change Management, Networking आदि।
- **शैक्षणिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी की अवसंरचना का निर्माण–** भारत सरकार द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 सरकारी कन्या विद्यालयों एवं 8 महाविद्यालयों में 10–10 कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं। 2000 अन्य विद्यालयों में भी इस वित्तीय वर्ष में कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गयेहै।
- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.

सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगा उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जायेगा।

- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर. के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन

- स्टेट डाटा सेन्टर – एन.ई.जी.पी के अन्तर्गत राज्य के नये सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नवीन डेटा सेन्टर का निर्माण किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्टेट डाटा सेंटर उद्घाटन दिनांक 15.12.2010 को किया गया एवं तत्समय से यह क्रियाशील है। सम्पूर्ण परियोजना

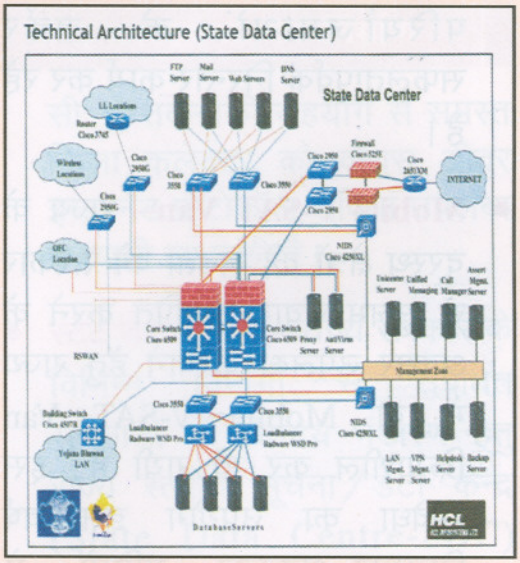

भारत सरकार द्वारा पोषित की जा रही है।

- राज्य सरकार ने संचार आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिकतम बनाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभाव का विकास होगा। RajSWAN परियोजना के लिये केन्द्र सरकार के

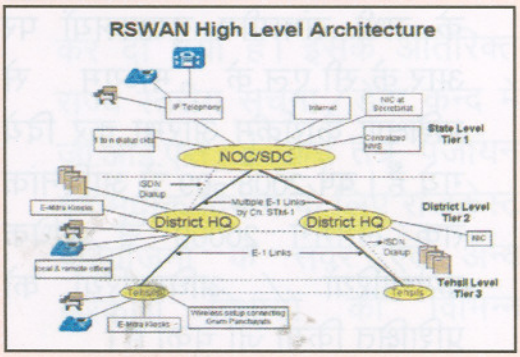

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एन.ई.जी.पी. परियोजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2005 को रूपये 96.62 की वित्तीय स्वीकृती दी गयी। परियोजना का क्रियान्वयन पांच वर्षो में कर दिया जायेगा।

वर्तमान स्थितिः

- भारत सरकार से आदिनांक तक रूपये 28.90 करोड़ प्राप्त हो गये हैं।
- दिनांक 20.12.2010 तक 31.59 लाख रूपये उपयोग में लिये गये हैं।
- इस परियोजना द्वारा प्रदेश के 33 जिलों व 250 तहसीलों को राज्य मुख्यालय से जोड़ा जायेगा। वर्टिकल सेगमेन्ट की कुल लागत भारत सरकार द्वार पोषित की जायेगी।
- हॉरीजेन्टल सेगमेन्ट के अन्तर्गत 3381 कार्यालयों को जोड दिया जायेगा। इसकी कुल लागत पांच वर्षो के लिये रुपये 102 करोड है। यह लागत राज्य सरकार द्वारा पोषित की जायेगी।
- निविदा प्रपत्रों के मूल्यांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा कार्यादेश 31 मार्च 2011 तक जारी होना एवं परियोजना का क्रियान्वयन माह मार्च 2012 के अंत तक आरंभ होना संभावित है।

- **स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे** – भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2009 को 11.51 करोड की वित्तीय स्वीकृती जारी की गयी। राष्ट्रीय ई–प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जाना है।

वर्तमान स्थितिः

- इस परियोजना के लिए भारत सरकार से आदिनांक तक राशि रूपये 3.70 करोड़ प्राप्त हो गये हैं।
- 20.12.2010 तक रुपये 4.27 लाख उपयोग किये गये हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा चयनित सलाहकार मै. आई.एल.एफ.एस. ने अन्तरिम गेप रिर्पोट तैयार की है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। इस योजना के द्वितीय चरण

के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स के.पी. एम.जी. को कन्सलटैंट नियुक्त किया गया।

- इस परियोजना के अंतर्गत कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्यान, ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा विभाग तथा जयपुर कलेक्टर कार्यालय की मुख्य परियोजनाओ का कम्प्यूटरीकरण हेतु चयन किया गया है।
- मै0 विप्रो टेक्नोलोजी लि0 को दिनांक 20.12.2010 को रूपये 10.46 करोड का कार्यादेश जारी किया गया है जिसकी अवधि 3 वर्ष है।
- परियोजना का क्रियान्वयन सितम्बर 2011 तक कर दिया जायेगा।

- **जिला स्तर पर टच स्क्रीन कियोस्क की स्थापना–** आम जनता को सुलभता से सरकारी सूचनाऐं एवं सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु 33 जिला कलेक्टर कार्यालयों एवं सभी संभागीय मुख्यालयों पर कियोस्क लग गये हैं। टच स्क्रीन कियोस्क पर आम जनता को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु व्यक्तिगत लाभांश योजनाऐं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री सहायता योजना एवं अन्य ऐसी योजनाओं की सूचना वॉयस ओवर सुविधा के साथ डालकर परियोजना प्रारम्भ कर दी गयी है।

  - प्रथम चरण में व्यक्तिगत लाभांश योजनाओं से संबंधित विभिन्न प्रपत्र प्रिन्ट करने की सुविधा एक साधारण लेजर प्रिन्टर के द्वारा जयपुर कलेक्ट्रेट में पॉयलेट आधार पर उपलब्ध करवा दी गयी है।

- **ई–संचार–** परियोजना के अर्न्तगत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वॉयस कॉल/एस.एम.एस के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सूचनाओं की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओ, विशेष रूप से पेंशनर्स को सूचना का प्रसार किये जाने में मदद मिलेगी। पेंशन संवितरण से संबंधित सूचना के

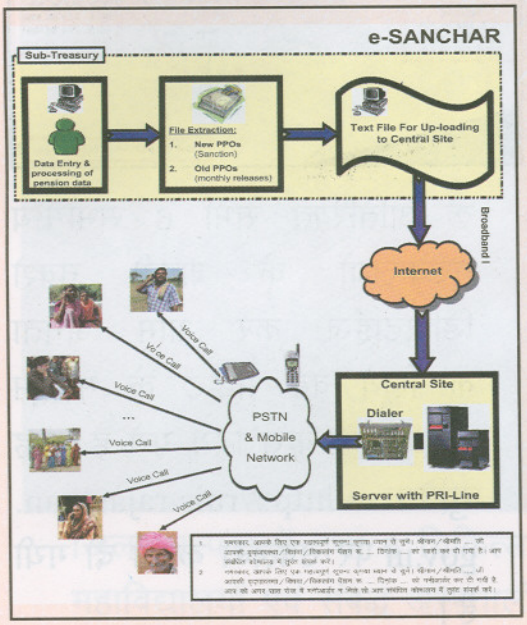

प्रसार के लिए ई–संचार परियोजना को जयपुर जिले के समस्त 13 उप कोषालयो में लागू कर दिया गया है।

- इस परियोजना को Maximum Social Impact by PC Quest के अन्तर्गत Best IT Implementation Award 2009 से पुरस्कृत किया गया।

- **जन सेवा केन्द्र (Common Service Cenre)**– राज्य के समस्त सात संभागों पर इस परियोजना का क्रियान्वयन M/s CMS and M/s Zoom Technologies के माध्यम से शुरू हो गया है। परियोजना के अंर्तगत कुल 6626 नागरिक सेवा केन्द्र राज्य में खोले जाने हैं। दिनांक 20.12.2010 तक कुल 1894 केन्द्र कियोस्क व्यापार से नागरिक सेवाओं हेतु प्रारंभ कर दिये गये हैं

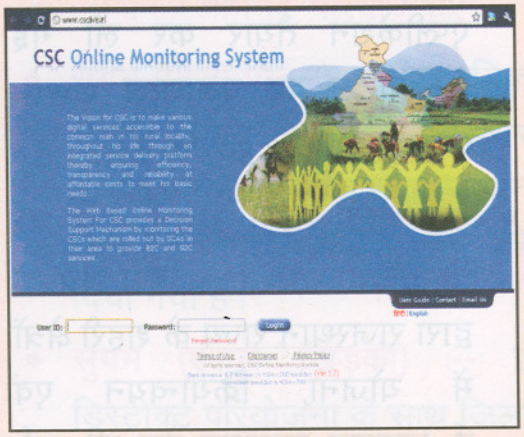

जिसके अंतर्गत रेलवे रिज़र्वेशन, बस रिज़र्वेशन, नवीन बीमा पॉलिसी पंजीयन, सभी प्रकार के मोबाइल रीचार्ज समस्त डी.टि.एच रीचार्ज, टाटा स्काई सेट टॉप बाक्स का विक्रय एवं आईटीज़ेड रीचार्ज किये जा रहे हैं। कार्यशील केन्द्रों में से 1677 केन्द्रों पर सरकार से नागरिक सेवाऐं भी उपलब्ध हैं।

इस प्रबोधन तंत्र द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्वचालित हो गयी है एवं निरिक्षण अधिकारियों द्वारा तुरन्त ही प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहें है। सीएससी परियोजना के अन्तर्गत यह एक अनूठी पहल है।

ग्रामीण स्तर तक सीएससी परियोजना के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिये वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। पोर्टल का यूआरएल www.cscmis.emitra.gov.in है।

- **राजस्थान शहरी सूचना तंत्र का क्रियान्वयन (RUIS)–** इस तंत्र के द्वारा राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना, क्रियान्वयन एवं ई–प्रशासन समाधान हेतु जी.आई.एस. यंत्र एवं नक्शे उपलब्ध होंगें। प्रथम चरण में भरतपुर संभाग

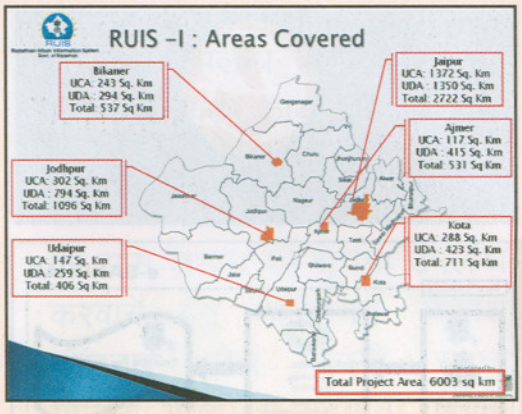

के अतिरिक्त सभी 6 संभागीय मुख्यालयों के शहरी नक्शे डिजिटाईज कर आम जनता के लिये वेब साईट के माध्यम से उपलब्ध करा दिये गये है। यह सुविधा http://ruis.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गयी है।

- **आरोग्य ऑन लाइन–** सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की पूर्ण कम्प्यूटरीकरण परियोजना वर्तमान में जारी है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में इमरजेंसी, आउट पेशेंट पंजीयन, बिलिंग, जांच (सेंट्रल लैब), इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट, पूछताछ तथा फार्मेसी एवं दवा विभाग को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस परियोजना को शीघ्र ही सभी 15

जिला अस्पतालों तथा 6 चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों में लागू किया जावेगा। इस हेतु राजकॉम्प एवं सी–डेक के मध्य दिनांक 24.06.2010 तथा 8.12.2010 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये।

- **नागरिक सेवा केन्द्र–** जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थापित नागरिक सेवा केन्द्र के आधार पर राज्य के 10 नगर सुधार न्यासों में नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहें हैं। इस सुविधा का समस्त 9 नगर सुधार न्यासों :–अलवर, कोटा, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं भिवाड़ी तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण में क्रियान्वयन कर दिया गया है।

नवीन/अभिनव परियोजनाऐं

- **सुगम (पीजी पोर्टल) :–** प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 11 विभागों में वेब एनेबल्ड जन अभियोग निवारण पोर्टल लागू कर दिया गया है।
- **सुगम (एकल खिड़की) :–** ई डिस्ट्रीक्ट परियोजना के साथ जिला कलक्टर/तहसील/उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों से संबंधित सेंवाओं की ई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तहसील/उपखण्ड मुख्यालयों तक ई सेवाओं का कार्यान्वयन कर दिया जायेगा।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

- पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के उददेश्य से पंचायतीराज विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तकनीकी सहयोग से भारत निर्माण राजीव गांधी विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना हेतु पंचायतीराज विभाग प्रशासनिक विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नोडल विभाग मनोनित किये गये है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19.11.2009 को दूदू पंचायत समति, दूदू में सबसे पहले भारतीय निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की नींव रखी गई।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भवन में नरेगा के परियोजना अधिकारी का कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा जिनकी देख–रेख में अन्य कार्यों के साथ–साथ नरेगा के

कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी संपादित किया जायेगा।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु निम्नलिखित स्त्रोत द्वारा वित्तीय प्रावधान किये जायेंगे:–

- NABARD
- NREGS
- Backward Region Grant Fund (BRGF)

नाबार्ड ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु 49.17 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया है।

ब्लाक स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की निर्माण लागत

25 लाख रूपये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपये है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की सिविल निर्माण लागत 21.80 लाख रूपये है तथा सोलर पावर बेकअप की निर्माण लागत 3.20 लाख रूपये है।

शहरी क्षेत्र मे आने वाले 124 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रो का निर्माण नाबार्ड एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता द्वारा किया जा रहा है (89 सेवा केन्द्र केवल नाबार्ड द्वारा एवं 35 सेवा केन्द्र नाबार्ड एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा)।

- **राजस्थान लोक सेवा आयोग :–** आयोग की गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा आई.टी. एनेबलमेंन्ट परियोजना प्रारम्भ की गई है। परियोजना के अन्तर्गत आयोग की समस्त गतिविधियॉ यथा ऑन लाईन आवेदन फार्म को डाउनलोड करने से परीक्षा परिणामों की घोषणा किये जाने के

साथ–साथ कार्यालय की अन्य सभी नियमित गतिविधियों के संचालन का कार्य किया जा सकेगा। परियोजना का कार्य 5 वर्षो में चरणबद्ध रूप से किया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 02.03.2010 को जारी किया गया एवं सम्पूर्ण कार्य फरवरी 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- **आई–फैक्टस (आई.टी. एनेबल्ड पूर्ण स्वचालित नागरिक आधारित पारदर्शी संस्थिति):–** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरो पर अनेक जी 2 सी सेवाऐं प्रदान की जाती है एवं इन सेवाओं के संबंध में नागरिको से प्रतिक्रिया/मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र प्रणाली की आवश्यकता

महसूस की गई जिससें सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार/संशोधन किया जा सके। आई–फैक्टस परियोजना के अंतर्गत स्वचालित प्रणाली स्थापित करने का प्रयास है जिससे टेलिफोन (मोबाईल टेलिफोन सहित) के माध्यम से नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना संभव हो सके।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं/ नीतियों/ कार्यकर्ताओं के संबंध में नागरिक/जन समितियों के विचार जानकर उन्हें शासन में सम्मलित करने के साथ–साथ आईवीआरएस तकनीक के माध्यम से एकीकृत आई.टी. समाधान हेतु प्रस्तावित योजनाओं को विभिन्न स्तर पर लागू करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से उनके विचार प्राप्त करना है।

- **यूनिक आईडेन्टिटीफिकेशन (यूआईडी) :–** सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को भारत सरकार के यूनिक आईडेन्टिटीफिकेशन पहल, जिसका प्रबंधन यूनिक आईडेन्टिटीफिकेशन ऑथिरीटी ऑफ इन्डिया द्वारा किया जा रहा है, हेतु पंजीयक के रूप में नॉमित किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य गतिविधियों जैसे यूआईडी नामांकन, नामांकन केन्द्रों की स्थापना, डेमोग्राफिक एवं बायोमेट्रीक आकड़ों एवं अन्य डाटा जो यूआईडीएआई द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वांछित हो का संकलन नॉमित पंजीयक द्वारा किया जावेगा। परियोजना की क्रियान्विति हेतु वांछित निविदा प्रपत्र तैयार कर लिया गया है।

❖❖❖

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2224855 • फैक्स : 0141-2222011
http://www.rajasthan.gov.in
http://www.doitc.rajasthan.gov.in

Macmillan Computers # 94142 36524